

क्रमांक 3311094 / छ.ग. / 2016 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 06 / 2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
3. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
4. हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर
5. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
6. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्या. प्रमुख अभि. जल संसाधन विभाग, रायपुर
7. परियोजना प्रशासक, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर
8. परियोजना प्रशासक, हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, बिलासपुर

विषय :- General election to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan. Transfer/Posting of Office Reg. पर भास्त्रनिर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 21.05.2018 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 1975 / 1897 / 31 / स्था. / 2018 दिनांक 07.06.2018.

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहपत्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। प्रकरण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लेख है, कि पत्र के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का अवलोकन एवं सूक्ष्म परीक्षण कर, पदस्थापना संबंधी प्रस्ताव सुस्पष्ट टीप/अभिमत/अनुशंसा सहित तत्काल उपलब्ध करावें एवं शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र. 3311094 / छ.ग. / 2016 / 10510
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 15/06/2018

1. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर को आयोग के संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर शासन के पत्र की छायाप्रति सहित विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
3. समस्त पटल-331 / 332

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-2) पत्र 3 के अति)


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

rule I

क्रमांक 1975/1897/31/स्था./2018
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक: 07-06-2018

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सिहावा भवन, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- General Election to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan. Transfer/Posting of Office Reg. पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 21.05.2018 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

---:000:---

उपर्युक्त विषयक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 18-1/2018/1/5 दिनांक 30.05.2018 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न है।

निर्देशानुसार उक्त प्राप्त पत्र में उल्लेखितानुसार प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर, अपने अभिमत/अनुशंसा सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव/जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

07 JUN 2018

6/6/2018

(राजीव अहिरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

आवक क्रमांक 5377
दिनांक 8-6-18

पंजी क्र... 82/12
ज.सं./20
दिनांक... 05.06.2018...2018

विधानसभा निर्वाचन
समय-सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन नया रायपुर

क्रमांक एफ 18-1/2018/1/5

नया रायपुर, दिनांक 30.05.2018

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर।

सयुक्त सचिव/ओएसडी
पूर्व निर्वाचन
31 MAY 2018

विषय:- General Election to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan Transfer/Posting of officers-reg. पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 21.05.2018 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 मई 2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 437/6/1/INST/ECI/FUNC/MCC/2018 दिनांक 21.05.2018 में दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत पालन निर्धारित समय-सीमा में करने के निर्देश दिये गये हैं।

2/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.05.2018 में विधान सभा निर्वाचन के संबंध में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी सुस्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े कोई भी अधिकारी गृह जिले में पदस्थ नहीं होने चाहिये, साथ ही उसे किसी स्थान विशेष में लंबे समय तक पदस्थ नहीं रहना चाहिये। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(i) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र की कंडिका-3 में निर्देशित किया गया है कि कोई भी अधिकारी जो निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े है, वह वर्तमान पदस्थापना जिले में निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य नहीं कर सकेगा :-

1. संबंधित जिला उसका गृह जिला है।
2. पिछले 04 साल में उस जिले में 03 वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थ रहा हो अथवा 31.01.2019 को या उससे पहले 03 वर्ष पूर्ण कर रहा हो।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र की कंडिका-4 अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/पुलिस इन्स्पेक्टर/सब-इन्स्पेक्टर अथवा उससे ऊपर के अधिकारियों को उस स्थान पर पदस्थ नहीं किया जायेगा जहां पिछले विधानसभा निर्वाचन/उप निर्वाचन में वह पदस्थ रहा हो।

दिनांक 05.05.18

जयक पत्र क्रमांक 333

सचिव, जल संसाधन विभाग,

दिनांक 05-06-18

(iii) यह निर्देश विनिश्चित निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचन कार्य विशेष के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी के अतिरिक्त जिलो के अन्य अधिकारी जैसे - ए.डी.एम., एस.डी.एम., डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, विकासखण्ड अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े समकक्ष अधिकारियों पर भी प्रभावशील होगा। इसी प्रकार पुलिस विभाग के लिये यह निर्देश रेंज आई.जी., डी.आई.जी., कमाण्डेंट, स्टेट आर्म्ड पुलिस, एस.एस.पी., एस.पी., ए.डी.ओ.(पी), एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, आर.आई, सार्जेंट मेजर तथा समकक्षीय अधिकारियों पर भी लागू होगा।

3/ पत्र की कोडिका-7 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पदस्थापना के संबंध में जारी स्पष्टीकरण तथा छूट दर्शित है, जिसका भली-भांति अध्ययन कर, निर्वाचन कार्य हेतु उपयुक्त एवं निष्पक्ष अधिकारियों को नियोजित किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना 30 जून 2018 तक जारी करने के निर्देश दिये गये हैं, तथा भारत निर्वाचन आयोग को पालन प्रतिवेदन जुलाई 2018 तक 1 सप्ताह के भीतर भेजा जाना है।

4/ अतएव भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित विस्तृत निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना दिनांक 20 जून 2018 तक अनिवार्यतः किया जाकर उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

R. Shan. 4179

(रीता शांडिल्य)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पंजी क्र.....1897
ज.स./20
दिनांक.....02-6-2018
छत्तीसगढ़ शासन

विधानसभा निर्वाचन /
समय-सीमा

13

सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन नया रायपुर

पु.
31/5/2018

क्रमांक एफ 18-1/2018/1/5

नया रायपुर, दिनांक 30.05.2018

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर।

संयुक्त सचिव/ओएसडी

सचिव

31/5/2018

31 MAY 2018

विषय:- General Election to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan Transfer/Posting of officers-reg. पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 21.05.2018 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 मई 2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 437/6/1/INST/ECI/FUNC/MCC/2018 दिनांक 21.05.2018 में दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत पालन निर्धारित समय-सीमा में करने के निर्देश दिये गये हैं।

2/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.05.2018 में विधान सभा निर्वाचन के संबंध में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी सुस्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े कोई भी अधिकारी गृह जिले में पदस्थ नहीं होने चाहिये, साथ ही उसे किसी स्थान विशेष में लंबे समय तक पदस्थ नहीं रहना चाहिये। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(i) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र की कंडिका-3 में निर्देशित किया गया है कि कोई भी अधिकारी जो निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े है, वह वर्तमान पदस्थापना जिले में निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य नहीं कर सकेगा :-

1. संबंधित जिला उसका गृह जिला है।
2. पिछले 04 साल में उस जिले में 03 वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थ रहा हो अथवा 31.01.2019 को या उससे पहले 03 वर्ष पूर्ण कर रहा हो।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र की कंडिका-4 अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/पुलिस इन्स्पेक्टर/सब-इन्स्पेक्टर अथवा उससे ऊपर के अधिकारियों को उस स्थान पर पदस्थ नहीं किया जायेगा जहां पिछले विधानसभा निर्वाचन/उप निर्वाचन में वह पदस्थ रहा हो।

(iii) यह निर्देश विनिश्चित निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचन कार्य विशेष के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी के अतिरिक्त जिलो के अन्य अधिकारी जैसे — ए.डी.एम., एस.डी.एम., डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, विकासखण्ड अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े समकक्ष अधिकारियों पर भी प्रभावशील होगा। इसी प्रकार पुलिस विभाग के लिये यह निर्देश रेंज आई.जी., डी.आई.जी., कमाण्डेंट, स्टेट आर्म्ड पुलिस, एस.एस.पी., एस.पी., ए.डी.ओ.(पी), एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, आर.आई, सार्जेंट मेजर तथा समकक्षीय अधिकारियों पर भी लागू होगा।

3/ पत्र की कंडिका-7 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पदस्थापना के संबंध में जारी स्पष्टीकरण तथा छूट दर्शित है, जिसका भली-भांति अध्ययन कर, निर्वाचन कार्य हेतु उपयुक्त एवं निष्पक्ष अधिकारियों को नियोजित किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना 30 जून 2018 तक जारी करने के निर्देश दिये गये हैं, तथा भारत निर्वाचन आयोग को पालन प्रतिवेदन जुलाई 2018 तक 1 सप्ताह के भीतर भेजा जाना है।

4/ अतएव भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित विस्तृत निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना दिनांक 20 जून 2018 तक अनिवार्यतः किया जाकर उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

R. Shan. 4179

(रीता शांडिल्य)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

महत्वपूर्ण / तत्काल

(15)

पंजी. क्र. 1896
ज.सं./20
दिनांक 02-06-2018

क्रमांक एफ 18-1/2018/1/5

नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2018

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर ।

पं.
सि.प्र.प.
82/31/18

विषय :- General Election to the State Legislative Assemblies of
Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan -
Transfer/Posting of officers- reg.

-0-

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक
437/6/1/INST/ECI/FUNC/MCC/2018, दिनांक 21.05.2018 की छायाप्रति
सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है ।

2/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लेख है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष
चुनाव हेतु पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के
पदस्थापना संबंधी उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन निर्धारित समय-सीमा में
कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

R. Shan-479

(रीता शांडिल्य)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा 0 क्रमांक एफ 18-1/2018/1/5

नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र दिनांक 21.05.2018 के संदर्भ में,
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त सचिव/ओएसडी

सचिव

R. Shan-479

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

28 MAY 2018

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No.437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2018

Dated: 21st May, 2018

To

The Chief Secretaries of:-

- (i) Chhattisgarh, Raipur;
- (ii) Madhya Pradesh, Bhopal;
- (iii) Mizoram, Aizawl;
- (iv) Rajasthan, Jaipur.

24 MAY 2018

✓ New, CIAD (RS.)

छत्तीसगढ़ शासन
स.प्र.वि. कम-5
पंजी. 3179
दिनांक 25/05/2018

Subject:-

General Election to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan - Transfer/Posting of officers - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the term of existing Legislative Assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan are up to 15th December, 2018, 5th January, 2019, 7th January, 2019 and 20th January, 2019, respectively.

2. The Commission has been following a consistent policy that officers directly connected with conduct of elections in an election going State/UT are not posted in their home districts or places where they have served for considerably long period.

3. Hence, the Commission has decided that no officer connected directly with elections shall be allowed to continue in the present district of posting:-

- (i) if she/he is posted in her/his home district.
- (ii) if she/he has completed three years in that district during last four (4) years or would be completing 3 years on or before
 - (a) 31.12.2018 in case of Mizoram; and
 - (b) 31.01.2019 in case of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan.

4. While implementing the above said instructions/transferring officers, the concerned departments of the State Govt. should take care that they are not posted to their home districts. It shall also be ensured that no DEO/RO/ARO/ Police inspectors/Sub-inspector or above is

7
posted back or allowed to continue in the AC /district where he/she was posted in last Assembly election/any bye election held thereafter.

5. If any small state/UT with a few number of districts, face any difficulty in compliance of the above instruction, then it may refer the specific case with reasons to the Commission through CEO for exemption and the Commission would issue directions, if considered necessary.

6. Applicability-

6.1 These instructions shall cover not only officers appointed for specific election duties like DEOs, Dy. DEOs, RO/AROs, EROs/AEROs, officers appointed as nodal officers of any specific election works but also district officers like ADMs, SDMs, Dy. Collector/Joint Collector, Tehsildar, Block Development Officers or any other officer of equal rank directly deployed for election works.

6.2 These instructions shall also be applicable to the police department officers such as Range IGs, DIGs, Commandants of State Armed Police, SSPs, SPs, Addl. SPs, Sub-Divisional Head of Police, SHOs, Inspectors, Sub-Inspector, RIs / Sergeant Majors or equivalent ranks, who are responsible for security arrangement or deployment of police forces in the district at election time.

7. Following clarifications/relaxations issued by the Commission, from time to time, are for information/guidance of all the concerned:-

- (i) The police officials who are posted in functional departments like computerization, special branch, training, etc. are not covered under these instructions.
- (ii) The Police Sub-Inspectors and above should not be posted in their home district.
- (iii) If a police sub-Inspector has completed or would be completing a tenure of 3 years out of four years on or before the cutoff date in a police sub-division, then he should be transferred out to a police sub-division which does not fall in the same AC. If that is not possible due to small size of district, then he/she should be transferred out of the district.
- (iv) During an election a large number of employees are drafted for different types of election duty and the Commission has no intention of massive dislocation of state machinery by large scale transfers. Hence, the aforesaid transfer policy is normally not applicable to officers/officials who are not directly connected with elections like doctors, engineers, teachers/principals etc. However, if there are specific complaints of

such govt. officer political bias or prejudice against any such govt. officer, which on enquiry, are found to be substantiated, then CEO/ECI may order not only for transfer of such official but also for appropriate departmental action against the said officer.

(v) The officers appointed as Sector Officer/Zonal Magistrate involved in election duties are not covered under these instructions. However, the observers, CEO/DEOs and ROs should keep a close watch on their conduct to ensure that they are fair and non-partisan in the performance of their duties.

(vi) While calculating the period of three years, promotion to a post within the district is to be counted.

(vii) These instructions do not apply to the officers posted in the State headquarters of the department concerned.

(viii) It is further directed that no officers/officials against whom the Commission had recommended disciplinary action in past and which is pending or which has culminated with a penalty or the officers who have been charged for any lapse in any election or election related work in the past, shall not be assigned any election related duty. However, an officer who was transferred during any past election under the Commission's order without any recommendation of disciplinary actions will not be just on this ground, considered for transfer, unless specifically so directed by the Commission. A copy of the Commission's instruction number 464/INST/2008-EPS dated 23rd December 2008 regarding tracking of names of tainted officers is enclosed. CEOs must ensure its compliance.

(ix) The Commission further desires that no officer/official, against whom a criminal case is pending in any court of law, be associated with/deployed on election related duty.

(x) Further, the Chief Electoral Officer of the State/UT shall invariably be consulted while posting the persons in place of present incumbents who stand transferred as per the above policy of the Commission. A copy of each of the transfer orders issued under these directions shall be given to the Chief Electoral Officer without fail.

(xi) The transfer orders in respect of officers/officials, who are engaged in the electoral rolls revision work, if any, during an election year shall be implemented only after final publication of the electoral rolls, in consultation with the Chief Electoral Officer concerned. In case of any need for transfer due to any extra ordinary reasons, prior approval of the Commission shall be taken.

4
19

(xii) Any officer, who is due to retire within the coming six months will be exempted from the above mentioned directions. Further, officers falling in the category (home/3+ criteria; if they are due to retire within 6 months) shall not be engaged for performing election duties without permission of the Commission.
(xiii) It is further clarified that all the officials of the State (except those posted in the office of the Chief Electoral Officer); who are on extension of service or re-employed in different capacities, will not be associated with any election related work.
(xiv) All election related Officers will be required to give a declaration in the format given below to the DEO concerned, who shall inform to CEO accordingly.

DECLARATION

DECLARATION

To be submitted within 2 days after the last date of nomination papers)

I, (Name) presently posted from (Date)
Do hereby make a solemn declaration, in connection with the current General/Bye election to Lok Sabha/ (Legislative Assembly that
(a) I am not a close relative of any of the contesting candidates in the current state/district election/leading political functionary of the state/district at the aforesaid election.
(b) No criminal case is pending against me in any court of law.
Note: If answer of (a) or (b) above is 'YES', then give full details in a separate sheet.
Dated.....
(Name) Designation

NOTE- Any false declaration made by any officer shall invite appropriate disciplinary actions.

8. The Commission's aforesaid instructions shall be brought to notice of the concerned departments/offices or State Govt. for their strict compliance. The DEO or concerned district officers shall ensure that officers/officials who are transferred should immediately handover their charge without waiting for their substitute.

9. The Commission has further directed that transfers/postings of all officers covered under the above instructions shall be done by 30th June 2018, and compliance reports with details of action obtained from the concerned departments/offices of State Government furnished to the Commission by first week of July, 2018.

10. Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,


(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

Copy to: Chief Electoral Officers of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan.


(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No 464/INST/2008/EPS

Date: 23rd December 2008

6
91

To
The Chief Electoral Officers
of all States/UTs

Subject: Tracking the names of officers transferred by the order of the Election Commission of India charged with dereliction of duty etc.

Reference: No.437/6/2006-PLN:III dated 6th November,2006 & ECI message No 100/1994-PLN:III dated 28.3.1994 addressed to the CEOs of all States & UTs

Sir/Madam,

The Election Commission of India vide the instruction referred to above had directed that a detailed review shall be undertaken before every election in all districts and all such officers should be posted out of their home districts or district where they have completed a tenure of 3 years out of 4 years, and had further directed that officers/officials against whom Commission has recommended disciplinary action or who have been charged for any lapse in election or election related work or who were transferred under the orders of the Commission in the matter may not be assigned to any election related duty.

However, it was observed during recent elections that in spite of efforts made by the CEOs and the DEOs to comply the above instruction of the Commission, there were still some instances of the officers who come under the above criteria and liable to be transferred out of the district to a non election related assignment but managed to stay back and the Commission came to know about this only at a later stage through complaints being raised by various political parties and members of public. These incidents, though few in numbers, send a wrong signal at the field level and non maintenance of proper information about the officers liable to be transferred on the above criteria has been recognised as a reason for some stray incidents of non-compliance. In order to remove the possibility of the occurrence of such incidents in future, the Commission has issued the following directions to make the existing instruction more effective:-

I. The CEO of the State shall maintain a register in which the information about IAS/IPS officers, DEOs, ROs and EROs transferred by the order of the Election Commission and against whom Commission has recommended disciplinary action or who have been charged for any lapse in election or election related work shall be maintained.

II. Similarly, the DEO will maintain a register containing information about other junior officers and other staff.

III. Within 7 days of the announcement of elections by the Election Commission of India the CEO of the State will send a compliance letter to the Zonal Secretary in the Commission confirming that all the officers coming under the above criteria have been transferred. Similarly he shall obtain a similar

coming under the above criteria have been transferred to non election related assignment and out of the district.

- IV. With reference to transfer of officers coming under '3 years out of 4 years criteria' and the home district criteria, DEOs shall ensure compliance in respect of ROs, EROs, AROs and AEROs and other election related officials and send a letter to CEO within the time, if any, stipulated for this purpose by the Election Commission of India or CEO and if not, within 7 days of issue of press note announcing the elections. Similarly, information related to DEOs, SSP and SPs and other senior police officials connected with the election work shall be maintained by the CEO and compliance by the State Govt shall be ensured at his level. Compliance regarding the transfer of these officers shall be collected from the DEOs and the CEO of the State shall send a consolidated letter of compliance to the Zonal Secretary within 7 days of the announcement of election.
- V. To facilitate the submission of this compliance letter within 7 days of the announcement of election, the CEO and DEO shall collect the information and ensure maintenance of register as stated above well in advance so that no time is lost.
- VI. There are many departments in the State Government that are involved in transferring officials and thereby accountable for the compliance of the above instructions of the Commission. The Commission's instruction regarding transfer of the officials during election shall be brought to the notice of the Secretaries of the departments concerned with a copy to the Chief Secretary. The Chief Secretary may be requested by the CEO to ensure that all the departments concerned comply with the Commission's instruction well in time.
- VII. With regard to bye-elections while the officers coming under the category dealt within para marked as (I) shall be transferred out of the district within three days of announcement of bye-election and certainly before the first days of receipt of nomination whichever is earlier.
- VIII. The above instruction be followed without any deviation.

Yours faithfully,

(SHANGARA RAM)
PRINCIPAL SECRETARY